Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बीच अंतर का अध्ययन

Shadhna Yadav[1]*, Dr. Umesh Kumar Yadav[2]

[1] Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

[2] Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

सार - 'जनजाति' शब्द का प्रयोग आम तौर पर एक सामाजिक रूप से एकजुट इकाई के लिए किया जाता है, जो उस क्षेत्र से जुड़ी होती है, जिसका सदस्य उन्हें राजनीतिक रूप से स्वायत्त मानता है। अक्सर एक जनजाति की एक अलग बोली और विशिष्ट सांस्कृतिक लक्षण होते हैं। जनजाति को "एक सामान्य नाम रखने वाले परिवारों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, एक सामान्य बोली बोलती है, एक सामान्य क्षेत्र पर कब्जा करने या कब्जा करने का दावा करती है और आमतौर पर अंतर्विवाही नहीं होती है, हालांकि मूल रूप से ऐसा हो सकता है। मूल रूप से इस अध्ययन में जिसके बारे में चर्चा की गई अनुसूचित जाति,व्यय , आय अंतर अनुपात

खोजशब्द - अनुसूचित, व्यय

----------X----------

परिचय

शब्द "अनुसूचित जाति" केवल कानूनी कल्पना और संवैधानिक मिथक है 1 इसे भारत के संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 341 इस प्रकार है:

'अनुसूचित जाति' का अर्थ ऐसी जातियों या जातियों या जनजातियों या ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के समूहों के कुछ हिस्सों से है जिन्हें अनुच्छेद 341 के तहत 'अनुसूचित जाति/संविधान के उद्देश्य के लिए माना जाता है। भारत में सभी आधिकारिक और गैर-सरकारी अभिलेखों में 'अनुसूचित जाति' और 'हरिजन' को पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि अनुसूचित जाति अछूतों का पर्याय नहीं हो सकती है, वास्तव में, बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों के साथ अछूतों के रूप में भेदभाव किया जाता है। जैसे, सभी प्रकार के भेदभाव से पीड़ित इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए, भारत का संविधान विकास की प्रक्रिया में बाकी भारतीयों के साथ पकड़ने में सक्षम बनाने के लिए विशेष रियायतें प्रदान करता है। इस संबंध में कुछ मामलों को उनके द्वारा झेली गई सामाजिक और आर्थिक अक्षमताओं के आधार पर अनुसूची में शामिल किया गया है। इन लोगों को 'अनुसूचित जाति' के रूप में जाना जाता है।[1]

अनुसूचित जातियाँ सदियों से सामाजिक-आर्थिक शोषण की शिकार रही हैं और उन्हें निम्न व्यवसायों, कम आय वाले व्यवसायों, अस्वच्छ वातावरण और दूषित शौकिया व्यवसायों में भेज दिया गया है। यद्यपि देश के कई हिस्सों में अस्पृश्यता प्रथा का क्षय हो रहा है, फिर भी जाति की कठोरता कई अनुसूचित जाति के मजदूरों को अशोभनीय व्यवसायों में सीमित कर देती है जो अन्य समुदायों की तुलना में उन्हें नुकसान में डालते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज में एक कठोर, व्यवसाय-आधारित, पदानुक्रमित जाति व्यवस्था थी जिसमें सामाजिक पदानुक्रम में किसी जाति का सापेक्ष स्थान उसके पारंपरिक व्यवसाय द्वारा निर्धारित किया जाता था। आज भी, बहुसंख्यक अनुसूचित जातियों के साथ हर तरह से भेदभाव किया जाता है और उन्हें पूंजी जैसी उत्पादक

www.ignited.in

संपत्ति के स्वामित्व से वंचित किया जाता है, साथ ही शिक्षा और समानता जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका अत्यधिक सामाजिक-आर्थिक अभाव बना रहता है।

भारतीय सामाजिक संरचना का नेतृत्व हिंदू जाति व्यवस्था द्वारा किया जाता है। जाति का तात्पर्य सामाजिक असमानता की एक कठोर प्रणाली से है जिसमें गतिशीलता के लिए प्रमुख बाधाएं या विविध स्तरों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। "जाति" शब्द की उत्पत्ति स्पैनिश शब्द "कास्टा" से हुई है, जिसका अर्थ है "नस्ल, नस्ल, नस्ल या विरासत में मिले गुणों का एक समूह"। पुर्तगालियों ने इस शब्द को भारत में लोगों के वर्गों से जोड़ा, जिन्हें 'जाति' के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी शब्द 'जाति' मूल शब्द 'कास्ट' का समायोजन है। वर्ग के आधार पर विभाजन एक सार्वभौमिक घटना है, लेकिन हिंदू जाति व्यवस्था की विशेषता यह है कि यह जन्म पर आधारित है न कि योग्यता पर। चार जातियों की बड़ी छतरी के नीचे ब्राह्मण (पुजारी), क्षत्रिय (रईस, सैनिक), वैश्य (कारीगर, व्यापारी) और शूद्र (श्रमिक बल), सैकड़ों और सैकड़ों उपजातियाँ हैं।[2]

शुद्धता और प्रदूषण की धारणा पर आधारित भारतीय जाति व्यवस्था का मानना था कि अनुसूचित जातियां अशुद्ध और प्रदूषित हैं। उन्हें मुख्यधारा के समाज से बाहर रखा गया और मंदिरों के भीतर रोक दिया गया, उच्च जाति के कुओं से पानी लाने और उच्च जाति के हिंदुओं के साथ सभी सामाजिक संचार। जाति व्यवस्था की कठोरता के कारण, अनुसूचित जातियों को बहिष्कृत, सीमांत, दलित, प्रदूषित माना जाता है और सदियों से उच्च जातियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है।

सदियों से, अनुसूचित जातियों में विभिन्न जाति समूह शामिल हैं, जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से पीड़ित हैं। वे सामाजिक पदानुक्रम में सबसे नीचे रहते हैं और प्राचीन काल से उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से उदास, विभेदित और शोषित हैं। 19वीं शताब्दी में, ज्योतिबा फुले ने 'दलित' शब्द का इस्तेमाल उन्हें जातिग्रस्त समाज के सबसे उत्पीड़ित और टूटे हुए पीड़ितों के रूप में वर्णित करने के लिए किया था। इन अछूतों या अनुसूचित जातियों को आधिकारिक तौर पर 1932 में दलित जातियों के रूप में परिभाषित किया गया था और उन्हें व्यवस्थित रूप से भारत की जनगणना (1931) में सूचीबद्ध किया गया था। अछूतों को 'हरिजन' नाम महात्मा गांधी ने दिया था। 'हरि' का अर्थ है 'भगवान' और 'जन' का अर्थ है 'लोग', यानी, 'भगवान के लोग', विभिन्न भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी और अन्य में इस शब्द का अर्थ 'एक बच्चा है जिसके पिता की पहचान रहस्यमय है'। इसलिए, इन जातियों द्वारा 'हरिजन' नाम का विरोध और नफरत की गई थी।

भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है; और, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले लोगों के मामले में पहला सबसे बड़ा देश। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) दुनिया के कई देशों की तुलना में तेज दर से बढ़ रहा है। लेकिन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने, सोने और सड़कों के किनारे शौच करने और भीख मांगने की आबादी भी बढ़ती जा रही है। भारत में विश्व स्तरीय धनवानों की संख्या बढ़ रही है; लेकिन गरीबी का स्तर कम नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी के बीच गरीबी का स्तर और गरीबी की घटनाएं अधिक हैं।

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आधिकारिक तौर पर लोगों के नामित समूह हैं और भारत में सबसे वंचित सामाजिक-आर्थिक समूहों में से हैं। शर्तों को भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है और समूहों को एक या अन्य श्रेणियों में नामित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की अधिकांश अवधि के लिए, उन्हें दलित वर्गों के रूप में जाना जाता था।

आधुनिक साहित्य में, अनुसूचित जातियों को कभी-कभी दलित के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है "एकजुट / एक साथ समूहित", जिसे बी.आर. अम्बेडकर (1891-1956), एक दलित स्वयं, एक अर्थशास्त्री, सुधारक, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। , और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दलित नेता। अम्बेडकर ने गांधी के शब्द हरिजन के स्थान पर दलित शब्द को प्राथमिकता दी, जिसका अर्थ है "हरि/विष्णु का व्यक्ति" (या भगवान का आदमी)। सितंबर 2018 में, सरकार ने "सभी निजी उपग्रह चैनलों को एक एडवाइजरी जारी कर उन्हें 'दलित' नाम का उपयोग करने से 'बचाने' के लिए कहा", हालांकि "अधिकार समूह और बुद्धिजीवी लोकप्रिय उपयोग में 'दलित' से किसी भी बदलाव के खिलाफ सामने आए हैं"[3]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भारत की आबादी का क्रमश: लगभग 16.6% और 8.6% शामिल

www.ignited.in

है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 अपनी पहली अनुसूची में 28 राज्यों में 1,108 जातियों को सूचीबद्ध करता है, और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 अपनी पहली अनुसूची में 22 राज्यों में 744 जनजातियों को सूचीबद्ध करता है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का दर्जा दिया गया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई, और संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सकारात्मक भेदभाव के सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करता है।[4]

व्यय

व्यय को फसल की खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और उपभोग में बांटा गया है। खपत को आगे भोजन और गैर-खाद्य में विभाजित किया गया है। भोजन में चावल, बाजरा, मसाले, मांस, नशीला पदार्थ और खाने के लिए तैयार भोजन शामिल हैं। गैर-खाद्य व्यय में कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन और विविध वस्तुएं शामिल हैं। वेल्लार समुदाय के लिए ये सभी व्यय मदें बड़ी हैं। चूंकि सन्नार पास के जंगल में रहते हैं, इसलिए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वेल्लालर उत्तरदाताओं को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। वेल्लार उत्तरदाताओं ने निजी अस्पतालों को प्राथमिकता दी। सन्नार समुदाय के उत्तरदाता मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। वेल्लालर उत्तरदाता अधिक बार प्रवास करते हैं उपभोग करने के लिए आने से अधिकांश सन्नार शाकाहारी होते हैं जबकि सभी वेल्लालर मांसाहारी भोजन भी खाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में ऐसी कोई दुकान नहीं है जो खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ बेचती हो। उत्तरदाताओं को तैयार खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए 20 किमी से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है। जब भी वे आस-पास के शहरों में जाते हैं। वे ज्यादातर तैयार खाद्य पदार्थ और सब्जियां खरीदते हैं। गांव की दुकानों में बीड़ी और सिगरेट सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं।[5-6]

अन्य खाने योग्य और उपभोग्य सामग्रियों के लिए, उत्तरदाता पास के शहर जम्मूनामट्टूर के बाजारों पर निर्भर हैं। पुलियुर (अध्ययन क्षेत्र) और चेंगम (एक अन्य शहर) के बीच कोई बस सुविधा नहीं है। चेंगम जाने के लिए, उत्तरदाता दोपहिया वाहनों को प्राथमिकता देते हैं, अन्यथा उनके पास चेंगम के लिए बस पकड़ने के लिए 10 किमी के आसपास दो पैदल चलना होता है। जबकि जम्मूनामत्तूर के लिए बस की सुविधा ठीक है। इसलिए उत्तरदाता अपनी कटी हुई उपज, ज्यादातर समाई (एक बाजरा) जम्मूनामत्तूर बाजार में बेचने और अपनी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए लेते हैं।

साहित्य की समीक्षा

जोधका (2010) ने स्वरोजगार दलितों पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के बीच रोजगार पैटर्न के कुछ व्यापक संकेतों का अध्ययन किया। भारत में 16 प्रतिशत दलितों में से लगभग दो-तिहाई या तो पूरी तरह से भूमिहीन थे या लगभग भूमिहीन थे और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में आकस्मिक मजदूरी के रूप में काम करना जारी रखा था। लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि सभी 35 शहरी अनुसूचित जाति के परिवारों में से 29 प्रतिशत से कुछ अधिक एनएसएस के 61वें दौर के अनुसार स्वरोजगार की श्रेणी में थे। फील्डवर्क के लिए चुने गए कस्बों से पता चला कि यूपी में शहरी दलितों में 44 फीसदी से अधिक स्वरोजगार की श्रेणी में थे। और उनकी संख्या हरियाणा में राष्ट्रीय औसत (29.4) के बराबर कम थी। दलितों के पास आर्थिक और सामाजिक संसाधनों की कमी थी।[7]

थोराट (2010) ने कई सामाजिक रूप से वंचित समूहों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, खानाबदोश और गैर-अधिसूचित जनजातियों और अन्य बहिष्कृत समूहों के सामने आने वाली समस्याओं की प्रकृति पर चर्चा की; और उन नीतियों के मुद्दों को संबोधित किया जिन्हें सामाजिक बहिष्कार प्रेरित मानव गरीबी को संबोधित करने के लिए विकसित करने की आवश्यकता थी और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को बहिष्कृत समूहों की समूह-विशिष्ट समस्याओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए तर्क दिया। जाति की संस्था से जुड़े सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव से पीड़ित समूहों में पूर्व अछूत (अनुसूचित जाति) और अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल थे। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय राज्य ने सभी गरीबों के लिए "सामान्य कार्यक्रमों" का उपयोग किया था, जिसका उद्देश्य पूंजीगत संपत्ति के निजी स्वामित्व के माध्यम से या मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के माध्यम से आजीविका के स्रोतों तक पहुंच में सुधार करना था। [8]

www.ignited.in

राजीव एट अल। (2011) प्रमुख भारतीय राज्यों की तुलनात्मक तस्वीर और कर्नाटक का गहन विश्लेषण प्रदान करके एनएसएसओ के 59वें दौर से यूनिट रिकॉर्ड डेटा का उपयोग करके भारत में किसानों की ऋणग्रस्तता की प्रकृति और सीमा की जांच की। सर्वे देश के ग्रामीण इलाकों में किया गया। सभी सामाजिक समूहों में, अखिल भारतीय स्तर पर केवल 36 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के परिवार ऋणी थे, जबकि अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के संबंध में, ऋणग्रस्तता की घटना 50 प्रतिशत थी, और ओबीसी श्रेणी में 52 पर ऋण की घटना सबसे अधिक थी। प्रतिशत। महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों में उनके 36 पुरुष समकक्षों की तुलना में 42 प्रतिशत ऋणग्रस्तता की घटना थी, जो 50 प्रतिशत से पता चलता है कि न केवल सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों बल्कि महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों की भी तुलना में ऋण की खराब पहुंच थी। अन्य श्रेणियां। हालांकि अखिल भारतीय स्तर पर, उन राज्यों में व्यापक भिन्नता देखी गई जहां अनुसूचित जाति किसान परिवारों के लिए औपचारिक स्रोत से ऋण का हिस्सा कम था। महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के परिवारों के पास औपचारिक स्रोत से उनके क्रेडिट का 70 प्रतिशत से अधिक था। [9]

सिंह (2011) ने 2004-05 में किए गए भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण से लिए गए एक सूक्ष्म इकाई रिकॉर्ड किए गए प्रतिनिधि घरेलू सर्वेक्षण का उपयोग करके भारतीय ग्रामीण परिवारों में खेती की प्रति यूनिट शुद्ध कृषि आय में व्यवस्थित जाति-आधारित अंतर का विश्लेषण किया। परिणामों से पता चला कि भारत में औसत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को अन्य जातियों के परिवारों की तुलना में कम कृषि लाभ था; और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार अधिक वंचित समूह थे जिन्होंने उपभोग, शिक्षा और अन्य विकास सूचकांकों में औसत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की व्यापक कमी की सूचना दी। खेती के प्रतिफल में उनका नुकसान सार्वजनिक वस्तुओं और विभिन्न बाजारों तक पहुंच में सामाजिक बहिष्कार का परिणाम हो सकता है। गहन सर्वेक्षण में भारत भर के ग्यारह राज्यों में सिंचाई के पानी, विभिन्न सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक पहुंच वाले कुल गांवों के एक तिहाई से अधिक में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष भेदभावपूर्ण व्यवहार पाया गया।[10]

स्वामीनाथन और रावल (2011) ने अनुसूचित जाति के परिवारों और अन्य के बीच मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चार राज्यों के आठ गांवों के क्रॉस-सेक्शन से घरेलू डेटा वाले एक अद्वितीय डेटा सेट का उपयोग करके ग्रामीण भारत में आय के स्तर में असमानता को समझने में जाति की भूमिका की जांच की। विश्लेषण से पता चला है कि सभी गांवों में दलित परिवारों को उच्च आय वाले क्विंटल में कम प्रतिनिधित्व दिया गया था, और निचले क्विंटाइल में अधिक प्रतिनिधित्व किया गया था। परिवारों में आय असमानता ने प्रति व्यक्ति आय के लिए गिनी गुणांक के साथ अत्यधिक उच्च स्तर की असमानता दिखाई। ग्रामीण भारत में जातिगत भेदभाव के बने रहने के प्रमाण भी बढ़ते जा रहे थे। दलितों बनाम अन्य लोगों के लिए आय के बारंबारता वितरण ने अलग-अलग गैर-अतिव्यापी खंडों का खुलासा किया। अधिक समृद्ध कृषि गांवों में उच्च आय असमानता के साथ-साथ चिह्नित जाति अलगाव द्वारा 37 की विशेषता थी। एक गाँव में दलित आबादी के आकार ने अंतर-समूह असमानता की डिग्री के साथ कोई साधारण संबंध नहीं दिखाया[11]

कृष्ण (2012) ने जांच की कि क्या राज्य के प्रत्येक जिले में अनुसूचित परिवारों ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार किया है या नहीं। यह सर्वे वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया गया था। योजनाओं के प्रभाव के विश्लेषण से अध्ययन के सभी जिलों में शिक्षा के स्तर में 60 प्रतिशत से अधिक का सुधार सामने आया। पूरे राज्य में केवल 8 प्रतिशत लाभार्थियों ने अपनी जनसांख्यिकीय स्थिति को स्थानांतरित किया था, जबकि 92 प्रतिशत ने अपनी जनसांख्यिकीय स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने की सूचना दी थी। ऋण समय के दौरान सर्वेक्षण के समय आय में प्रतिशत वृद्धि ने लाभार्थियों की आय में 61 से 121 प्रतिशत की वृद्धि का खुलासा किया। परिसम्पत्तियों में सुधार के विश्लेषण से पता चला कि सभी जिलों में ऋण के समय सर्वेक्षण के समय लाभार्थियों की संपत्ति की स्थिति में भी सुधार हुआ था। इसके अलावा, लाभार्थियों के जीवन स्तर में भी उनकी आय में वृद्धि के साथ वृद्धि हुई थी। कुल मिलाकर, विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत एचपीएससी / एसटीडीसी सोलन द्वारा सहायता प्राप्त लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता का उपयोग करने के बाद अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में वृद्धि दिखाई थी।[12]

www.ignited.in

मैरियप्पन (2012) ने महानगरीय शहर चेन्नई में शहरी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रम बाजार में एक प्राथमिक सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करते हुए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित जाति के पुरुष श्रमिकों के बीच वेतन अंतर की जांच की। यह देखा गया कि अधिकांश गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के श्रमिक जिनके पास समान श्रम बाजार अनुभव और मानव पूंजी बंदोबस्ती विशेषताएँ थीं, उनके नियोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कम मजदूरी प्राप्त करने की प्रवृत्ति थी। वर्णनात्मक विश्लेषण से पता चला है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के बीच अंतर वेतन रु। 63. एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ता ने अपने समकक्ष की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत कम अर्जित किया। इसी तरह, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक प्रवासी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूह से संबंधित गैर-प्रवासी से संबंधित एक प्रवासी की तुलना में प्रति दिन लगभग रु। 70 लेखांकन लगभग 36 प्रतिशत। औपचारिक शिक्षा और अनुभव के वर्ष में वृद्धि ने सभी श्रमिकों की कमाई में वृद्धि की। शिक्षा के प्रभाव ने सुझाव दिया कि शिक्षा के एक अतिरिक्त वर्ष में औसतन प्रति घंटा वेतन में लगभग 0.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामों ने सुझाव दिया कि मानवीय कारकों, अर्थात् शिक्षा, अनुभव और प्रशिक्षण का कमाई और मजदूरी पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा [13]

खातून (2013) ने 1911 से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की शैक्षिक स्थिति को उजागर करने का प्रयास किया। भारत में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित आबादी के बीच शैक्षिक अवसरों में व्यापक असमानता थी। अनुसूचित जाति के केवल 6.97 प्रतिशत साक्षर थे, जबकि कुल जनसंख्या में साक्षरता 17.34 प्रतिशत थी। 2001 में भी, 39 राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में साक्षरता 36.75 प्रतिशत थी, जबकि कुल जनसंख्या में साक्षरता 45.56 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर 1961 में 1.54 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 22.22 प्रतिशत हो गया। इस संबंध में महिला शिक्षा प्राप्ति की स्थिति दयनीय थी। 1961 में, मैट्रिक और उससे ऊपर के स्तर पर शिक्षित कुल अनुसूचित जातियों का केवल 0.29 प्रतिशत, जबकि 2001 में, स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ और उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 12.84 प्रतिशत और अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या 5.59 प्रतिशत हो गई। जाति-वार विश्लेषण से यह भी पता चला कि कुल अनुसूचित जाति की आबादी का 56 प्रतिशत हिस्सा चमार जाति की कुल आबादी का केवल 1.66 प्रतिशत शैक्षिक प्राप्ति में और 1991 में 5.86 प्रतिशत था। इसलिए, शैक्षिक विकास के निम्न स्तर के बीच समाज के विभिन्न स्तरों ने उनके बीच सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण और प्रभाव दोनों पर विचार किया [14]

पद्धति

मध्य प्रदेश का एक जिला सागर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बीच अंतर को समझने के लिए अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले स्थान का चयन किया जाएगा।

नमूना

उपरोक्त वर्णित परिवारों में से 113 घरों का एक नमूना यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। नमूना परिवारों से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों के अलावा, अध्ययन गांव का पता लगाने और अध्ययन क्षेत्र की रूपरेखा का वर्णन करने के लिए माध्यमिक डेटा का उपयोग किया जाएगा।

अध्ययन का दायरा

गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के बीच अंतर को समझने से अनुसूचित जनजातियों के बीच गरीबी को कम करने के लिए उचित नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। अब तक, सरकारी लाभों के वितरण के पैटर्न पर व्यापक चर्चा हो रही है। एक विचार यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ हॉल में जाने चाहिए, यानी सार्वभौमिक कवरेज। दूसरा विचार यह है कि लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को जाना चाहिए। दोनों दृष्टिकोणों को ताकत और कमजोरी मिली है। गरीबी रेखा से ऊपर के घरों में गरीबी रेखा से नीचे के घरों से काफी अलग नहीं हैं, तो यूनिवर्सल कवरेज बेहतर है। लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण की कमियों से बचा जा सकता है। इसमें प्रस्तुत अध्ययन उपयोगी होगा।

डेटा विश्लेषण

बीपीएल और एपीएल रहने वाले परिवारों के बीच अंतर

1. परिवारों की प्रकृति

परिवार की प्रकृति की दृष्टि से इनमें कोई सार्थक अन्तर नहीं है। दोनों समूहों में एकल परिवारों का अनुपात संयुक्त परिवारों के अनुपात से थोड़ा अधिक है। इसलिए परिवार की प्रकृति उनकी आर्थिक स्थिति की व्याख्या नहीं करती है। औसत परिवार का आकार एपीएलएच (3.5 सदस्य) की तुलना में बीपीएलएच (4.5 सदस्य) में बड़ा है। यह बीपीएलएच में प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण हो सकता है।

2. शिक्षा

आम तौर पर कम साक्षरता का मुख्य कारण खराब परिवहन सुविधाएं और सड़कें हैं। सरकार द्वारा केवल तीन बस यात्राएं प्रदान की जाती हैं। निजी मिनी बसें दिन में केवल दो बार पुलियूर आती हैं। दो स्कूल हैं। सबसे पहले, वन आवासीय विद्यालय को चर्चा के लिए लिया जाता है। स्कूल का छत क्षेत्र 2,200 वर्ग फुट है। 140 छात्र हैं - 40 फीसदी लड़कियां और 60 फीसदी लड़के पढ़ रहे हैं। आठ शिक्षक हैं। तीन शिक्षकों के वेतन का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है और शेष पांच शिक्षकों का भुगतान एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। इस स्कूल में छात्र 8वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें किसी और स्कूल में जाना पड़ता है। इस स्तर पर बड़ी संख्या में ड्रॉपआउट हैं। इस स्कूल में सभी लड़कियों को रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। 500 प्रति वर्ष। पेयजल की सुविधा है। शौचालय उपयोग योग्य स्थिति में नहीं हैं। इसलिए छात्र शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं।

अन्य स्कूल अर्थात् कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इनमें आठ शिक्षक और 80 छात्र हैं। सभी आठ शिक्षकों के वेतन का भुगतान केंद्र सरकार करती है। केवल लड़कियों की अनुमति है। लड़कियां किसी न किसी रूप में वंचित वर्ग से हैं। वे अनाथ, बाल श्रमिक, खराब प्रदर्शन करने वाले आदि हैं, पीने का पानी और शौचालय उपलब्ध हैं। हालांकि, छात्र खुले में शौच करना पसंद करते हैं।

परिवारों के दो समूहों में निरक्षरता के संदर्भ में कुछ अंतर हैं। बीपीएलएच (बीपीएलआर) के 70 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता निरक्षर हैं। एपीएलएच (एपीएलआर) के उत्तरदाताओं के लिए यह प्रतिशत केवल 54 है। विश्वविद्यालय की डिग्री के साथ, यह माना जा सकता है कि कुछ एपीएलएच को बेहतर कमाई वाली नौकरी मिल सकती है और इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बीपीएलआर की तुलना में थोड़ी बेहतर हो सकती है। हालाँकि, अध्ययन क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है! बीपीएलआर और एपीएलआर के बीच रोजगार की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसलिए यह आर्थिक स्थिति है जिसने शैक्षिक स्थिति को प्रभावित किया है, न कि इसके विपरीत। इस गांव के छात्रों को अन्य लोगों की तरह विश्वविद्यालय की डिग्री तो मिलती है, लेकिन उन्हें बेहतर नौकरी नहीं मिल पाती है। या तो छात्रों के कौशल का स्तर बहुत कम है या रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं या दोनों। यहां कोई निर्णायक बयान देना मुश्किल है। लेकिन मैक्रो स्तर के आंकड़ों को देखते हुए, यह धीरे-धीरे छात्रों के कौशल में सुधार के मामले में अपना महत्व खो रहा है। पूर्वावलोकन अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि विशेष रूप से मध्य या माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद स्कूली शिक्षा में आदिवासी बच्चों का ड्रॉप-आउट बहुत अधिक था। मलयाली आदिवासी समुदाय में सामान्य जनसंख्या और व्यापक असमानता की तुलना में साक्षरता का स्तर बहुत कम है।

3. रोज़गार

रोजगार के प्रमुख स्रोत कृषि हैं, महिला श्रमिकों के लिए मजदूरी दर लगभग 100 रुपये प्रति दिन है। पुरुष अन्य राज्यों, विशेष रूप से केरल और आंध्र प्रदेश में प्रवास करना पसंद करते हैं, जहां वेतन तीन गुना अधिक है। गांवों में वे कुछ कृषि कार्यों में संलग्न हैं, जहां उन्हें प्रतिदिन 2,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। वे ज्यादातर लकड़ी काटने के काम के लिए आंध्र प्रदेश जाते हैं। केरल में वे निर्माण गतिविधियाँ करते हैं। चेय्यर, कोयम्बटूर और तिरुपुर में कताई मिलें कुछ लड़कियों को नौकरी देती हैं। अधिकतर वे वहाँ लगभग तीन महीने रहते हैं, और शेष नौ महीने वे कुछ कृषि कार्य करते हैं। मनरेगा रोजगार के पर्याप्त अवसर भी प्रदान करता है। वे वन उत्पादों को भी इकट्ठा करते हैं और पैसा बनाने के लिए बाजार में बेचते हैं।

आय अंतर अनुपात

आय अंतर अनुपात दर्शाता है कि समुदायों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। वेल्लार और सन्नार का आय अंतर अनुपात क्रमशः रु 6,096.86 और 7,213.59 रुपये।

तालिका 1 पारिवारिक विवरण

www.ignited.in

क्रमांक	वस्तु	बीपीएल	एपीएल
1	आय सीमा (प्रति दिन, प्रति व्यक्ति)	≤Rs.18,250	Rs. 18,251≥
2	परिवारों की संख्या	76	37
3	व्यक्तियों की संख्या	349	130
4	सनार परिवारों की संख्या	30	4
5	वेल्लालर परिवारों की संख्या	46	33
6	संयुक्त परिवारों की संख्या	35	15
7	एकल परिवारों की संख्या	41	22

स्रोतः क्षेत्र सर्वेक्षण से संकलित आंकड़े।

तालिका 2 उत्तरदाताओं की शिक्षा

क्रमांक	परिवारों के मुखिया/ प्रतिवादी की शिक्षा का स्तर	उत्तरदाताओं की प्रकृति	
		बीपीएल	एपीएल
1	निरक्षर	50	20
2	मुख्य	10 (13.15)	3 (8.10)
3	उच्च प्राथमिक	10 (13.15)	8 (21.62)
4	माध्यमिक	5 (6.57)	2 (5.41)
5	उच्च माध्यमिक	Nil	Nil
6	स्नातकीय	Nil	1
7	पीजी और इसके बाद के संस्करण	1 (1.31)	3 (8.10)
	कुल	76	37

स्रोतः क्षेत्र सर्वेक्षण से संकलित आंकड़े।

तालिका 3 उत्तरदाताओं के व्यवसाय

क्रमांक	उत्तरदाताओं के प्रमुख व्यवसाय	उत्तरदाताओं की प्रकृति			
		बीपीएल		एपीएल	
		मुख्य	माध्यमिक	मुख्य	माध्यमिक
1	कोई व्यवसाय नहीं	1(1.4)	2 (2.6)	निल	2 (5.4)
2	किसान	75 (98.6)	1 (1.3)	35(94.6)	निल
3	कृषि श्रमिक	निल	3 (3.9)	निल	1 (2.7)
4	सरकारी नौकरी	निल	1 (1.3)	निल	1 (2.7)
5	निर्माण कार्य	निल	35 (46.0)	2 (5.4)	19 (51.35)
6	मनरेगा	निल	34 (44.7)	निल	14 (37.83)
	कुल	76 (100)	76 (100)	37 (100)	37 (100)

स्रोतः क्षेत्र सर्वेक्षण से संकलित आंकड़े।

तालिका 4 घर के प्रकार

क्रमांक	घरों के प्रकार	उत्तरदाताओं की प्रकृति	
		बीपीएल	एपीएल
1	झोपड़ी	0	3 (8.10)
2	कुचा	10 (13.15)	2 (5.40)
3	अर्ध पक्के	33 (43.42)	16 (43.24)
4	पक्का	17 (22.36)	6 (16.21)
5	आईएवाई हाउस	16 (21.05)	10 (27.02)
	कुल	76 (100)	37 (100)

स्रोतः क्षेत्र सर्वेक्षण से संकलित आंकड़े। नोट: (आईएवाई) इंदिरा आवास योजना

तालिका 5 पेयजल कनेक्शन

क्रमांक	परिवारों का प्रकार	स्वयं का जल कनेक्शन	सार्वजनिक जल कनेक्शन
		हाँ	नहीं
1	बीपीएल परिवार (सं.)	57	19
2	एपीएल परिवार (सं.)	29	8
	कुल (सं.)	86	27

स्रोतः क्षेत्र सर्वेक्षण से संकलित आंकड़े।

अपेक्षित परिणाम

यह अध्ययन यह पता लगाने के लिए निर्धारित किया गया था कि क्या गरीब और गैर-गरीब परिवारों के बीच कोई अंतर है। पहले चरण में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कुल नमूना परिवारों को दो समूहों में विभाजित किया गया था। ये बीपीएलएच और एपीएलएच आय, व्यय,

www.ignited.in

भूमि आकार, बचत और उधार के मामले में भिन्न हैं। हालाँकि, वे अपनी जीवन शैली में भिन्न नहीं दिखते, जिसे आवास, शिक्षा, व्यवसाय आदि से दर्शाया जाता है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गांवों में गरीब और गैर-गरीब परिवारों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। गैर-गरीब परिवारों की अपेक्षाकृत बड़ी जोत, आय और व्यय का उनके जीवन स्तर में सुधार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। गांवों में परिवार उनकी आय और जोत के आकार के बावजूद लगभग समान हैं। इसलिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता है।

संदर्भ

थोराट, एस., और न्यूमैन, के.एस. (2007)। जाति और आर्थिक भेदभाव, कारण, परिणाम और उपचार। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, एक्सएलआईआई, 41, 4121-4124।

वानखेड़े, जी.जी. (1999)। अनुसूचित जातियों की सामाजिक और शैक्षिक समस्याएं: कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि। द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, 60 (3), 399-418।

शर्मा, एच. आर. (2006)। ग्रामीण भारत में ऋणग्रस्तता की घटनाएं: एक राज्य स्तरीय विश्लेषण। ग्रामीण विकास जर्नल, 25 (4), 507-536

सरवनन, वी. (2009)। तमिलनाडु का आर्थिक इतिहास: स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों के रहने की स्थिति, 1947-2007। द इंडियन इकोनॉमिक जर्नल, 57 (1), 57-79

प्रियदर्शी, आर.पी. (2011)। सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कानून - गुजरात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। पीएच.डी. थीसिस, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, गुजरात यूनिवर्सिटी, 91-92। 19 फरवरी 2014 को एक्सेस किया गया

पंजाब शासन सुधार आयोग (2011)। पंजाब शासन सुधार आयोग की सिफारिशें। पांचवी स्थिति रिपोर्ट, 158-179

जोधका, एस.एस. (2010)। व्यापार में दलित: उत्तर पश्चिम भारत में स्व-नियोजित अनुसूचित जाति। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज, वर्किंग पेपर सीरीज, 4 (2), 1-27।

थोराट, एस. (2010)। सामाजिक बहिष्करण और मानव गरीबी: समावेशी नीति के माध्यम से सुरक्षा। द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 53 (1), 23-39।

राजीव, एम., वाणी, बी.पी., और भट्टाचार्जी, एम. (2011)। भारत और कर्नाटक में किसानों की ऋणग्रस्तता की प्रकृति और आयाम। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, वर्किंग पेपर 267, बैंगलोर, 1-28।

सिंह, ए. (2011)। कृषि आय असमानता और जाति की भूमिका: भारत से नए साक्ष्य। आर्थिक बुलेटिन, 31 (4), 2847-2862।

स्वामीनाथन, एम., और रावल, वी. (2011)। ग्रामीण भारत में आय असमानता: जाति की भूमिका। ECINEQ, आर्थिक असमानता के अध्ययन के लिए सोसायटी, वर्किंग पेपर सीरीज़, 2-17।

कृष्ण, के. (2012)। लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर स्वरोजगार योजनाओं का प्रभाव: हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम। एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, 2 (5), आईएसएसएन 2249-7315।

मैरियप्पन, आर। (2012)। शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में जाति और मजदूरी का अंतर। मैन एंड डेवलपमेंट, 34 (3), 65-74।

खातून, एफ. (2013)। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की साक्षरता और शैक्षिक स्तर का क्षेत्रीय विश्लेषण। जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 6 (4), 08-19।

Corresponding Author

Shadhna Yadav*

Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

www.ignited.in